19 अप्रैल, 2018

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

ISSUE BRIEF

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य

डॉ तेमजेनमेरेन एओ और डॉ ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी*

सारांश

25 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, आसियान-भारत संबंधों के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सालाना उत्सव का भव्य समापन समारोह था। आसियान क्षेत्र को भारत के विस्तारित पड़ोस के रूप में माना जाता है, नमें दो सहस्राब्दियों से सभ्यतागत संबंध रहे हैं। आसियान राज्यों के दस प्रमुखों की मेजबानी ने एक तरह से भारत को संबंधों को फिर से सक्रिय करने में सक्षम बनाया है और इस क्षेत्र में नई चुनौतियों के साथ-साथ पुरानी चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान की है। इस पत्र में भारत-आसियान संबंधों के लिए रोडमैप प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख विषयों को भी शामिल किया गया है, जो शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे। प्रमुख परिणामों में से एक भारत और आसियान राज्यों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। समुद्री सुरक्षा और आसियान के साथ सहयोग को गहरा करने की दिशा में उठाया गया कदम एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत की स्थापना के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाएगा।

परिचय

भारत-आसियान संवाद साझेदारी के 25 साल पूरे होने का सालाना जश्न दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर तथा दस आसियान देशों के प्रमुखों का 69वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ संपन्न हुआ। उन्हें भारत की रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन के साथ-साथ भारत की सामाजिक- सांस्कृतिक विरासत की झलक मिली। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत आसियान देशों के कुछ प्रमुख रक्षा निर्यातकों में से एक है। आसियान देश के प्रमुखों को मुख्य अतिथि बनाने के भारत के रुख ने इसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति को बल प्रदान किया है। यह पहल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश स्थल के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण थी। आसियान नेताओं को पांच साल के भीतर दो बार साथ लाना मौजूदा संबंधों को अगले स्तर तक बढ़ाने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत वार्षिक शिखर बैठकों के अलावा तीस क्षेत्रीय संवाद तंत्र तथा सात मंत्रिस्तरीय बातचीत पहले ही हो चुकी है। भारत आसियान के अधिकांश देशों के साथ सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संबंधों को भी पोषित करता है जो लंबे और निरंतर संबंधों के आधार रहे हैं। इसने अर्थशास्त्र, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में संबंधों और सहयोग की श्रेणियों के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में मूल आधार प्रदान किया है।

भारत-आसियान संबंधों के तीन कारक

भारत-आसियान संबंधों में आज जो प्रगति देखी जा रही है, वह तीन व्यापक कारकों द्वारा निर्धारित की गई है, जिन्होंने संबंधों को मजबूत करने के दिशा में उत्प्रेरक के रूप में काम किया है।

आर्थिक कारक

शीतयुद्ध के बाद की अवधि में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भारत की विदेश नीति का मुख्य एजेंडा था। इस अवधि के दौरान भारत की घरेलू आर्थिक मंदी को देखते हुए दुनिया के एक आशाजनक विकास क्षेत्र के रूप में आसियान के उद्भव ने आर्थिक जुड़ाव के लिए बहुत संभावनाएं प्रदान कीं। 'पूर्व की ओर देखो' नीति के जरिये अपने पूर्वी पड़ोसियों तक भारत की पहुँच हो सकी। भारत आसियान देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध सुधारने में सक्षम था। जहाँ तक भारत का संबंध है, 1992 से लेकर चार साल से भी कम समय में, इसका दोतरफा व्यापार दोगुना से अधिक हो गया है; 1996-97 में, यह 6 बिलियन यूएस डॉलर रहा और वर्ष 2002 में 10 बिलियन यूएस डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया। भारत

के प्रमुख आसियान व्यापारिक साझेदार इंडोनेशिया , सिंगापुर और मलेशिया हैं। भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुओं में रत्न और आभूषण , दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मांस और मांस उत्पाद, चीनी, सूती धागे के कपड़े, गेहूं, मसाले और तैयार चमड़े शामिल हैं। आसियान से भारत के आयात में वनस्पति तेल , इलेक्ट्रॉनिक सामान , न्यूज़प्रिंट, प्राकृतिक रबर , मोती और कीमती पत्थर, और लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं। [i] बार आरेख बताता है कि कैसे नई सहस्राब्दी में, आसियान-भारत व्यापार निर्यात और आयात दोनों ही मामलों में वृद्धि का गवाह बना है। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार का आकार 1996-97 के बाद से दस गुना बढ़ा है, जो 2016 के अंत में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब रहा।

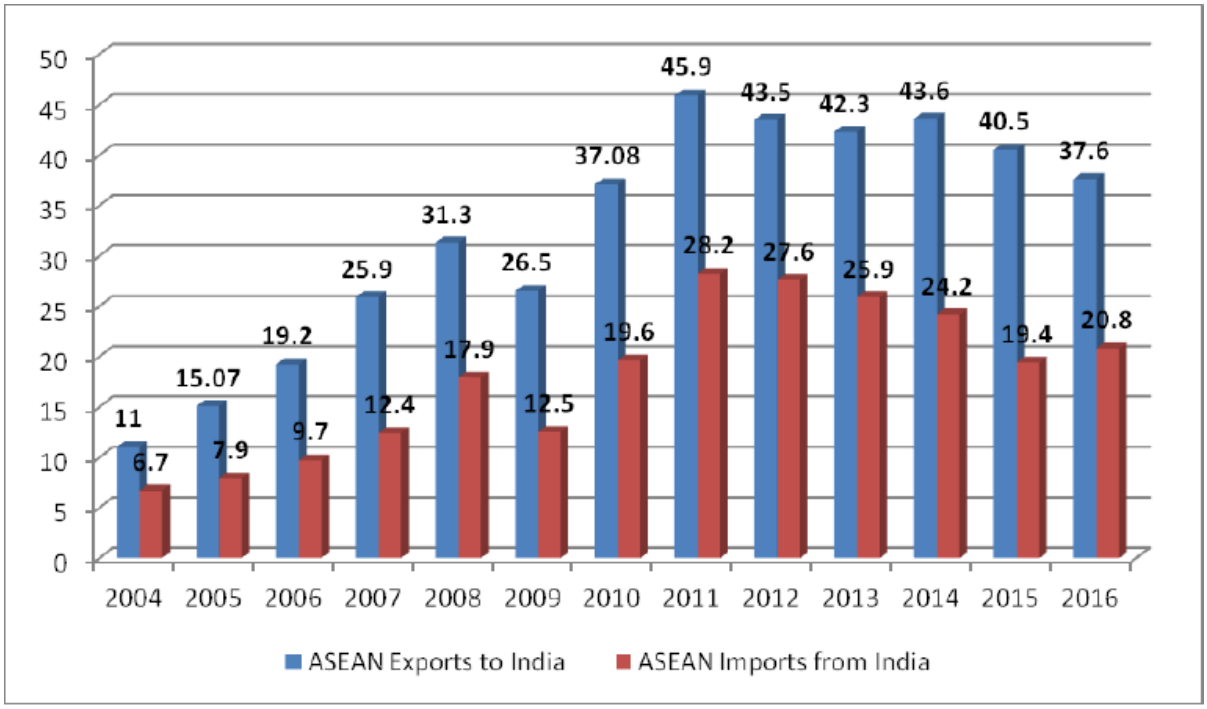

चित्र 1: भारत के साथ आसियान का व्यापार, 2006-2016 (अमेरिकी डॉलर में) [ii]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे आसियान राज्य - जो भारत में शीर्ष तीन आसियान निवेशक हैं - जहाँ बिजली और तेल रिफाइनरी, दूरसंचार, विद्युत उपकरण, आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, वहीं फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी में भी बड़ा निवेश प्रवाह हो रहा है। आसियान भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा निवेश बाजार है। भारतीय वैश्विक बाह्य एफडीआई (ओएफडीआई) स्टॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आसियान में है। इनमें से अधिकांश का प्रवाह सेवा क्षेत्र में है, मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) में। आसियान में भारतीय विनिर्माण ओएफडीआई मुख्य रूप से धातु और परिवहन उपकरण उद्योगों में है। भारत सीएलएमवी देशों के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विकासात्मक कोष की स्थापना के साथ-साथ मेकांग-गंगा सहयोग, बिम्सटेक जैसे विभिन्न उप- क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से संपर्क , भौतिक और डिजिटल के क्षेत्र में भी निवेश करता रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में विशाल और बढ़ते मध्यम वर्ग को बुनियादी ढाँचे के समर्थन की आवश्यकता है और इस प्रकार , भारत को न केवल भौतिक की दृष्टि से इन विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है , बल्कि क्षमता और क्षमता विकास के रूप में आसान निवेश भी प्रदान करता है। इसके अलावा , आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को आसियान बाजारों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।[iii]

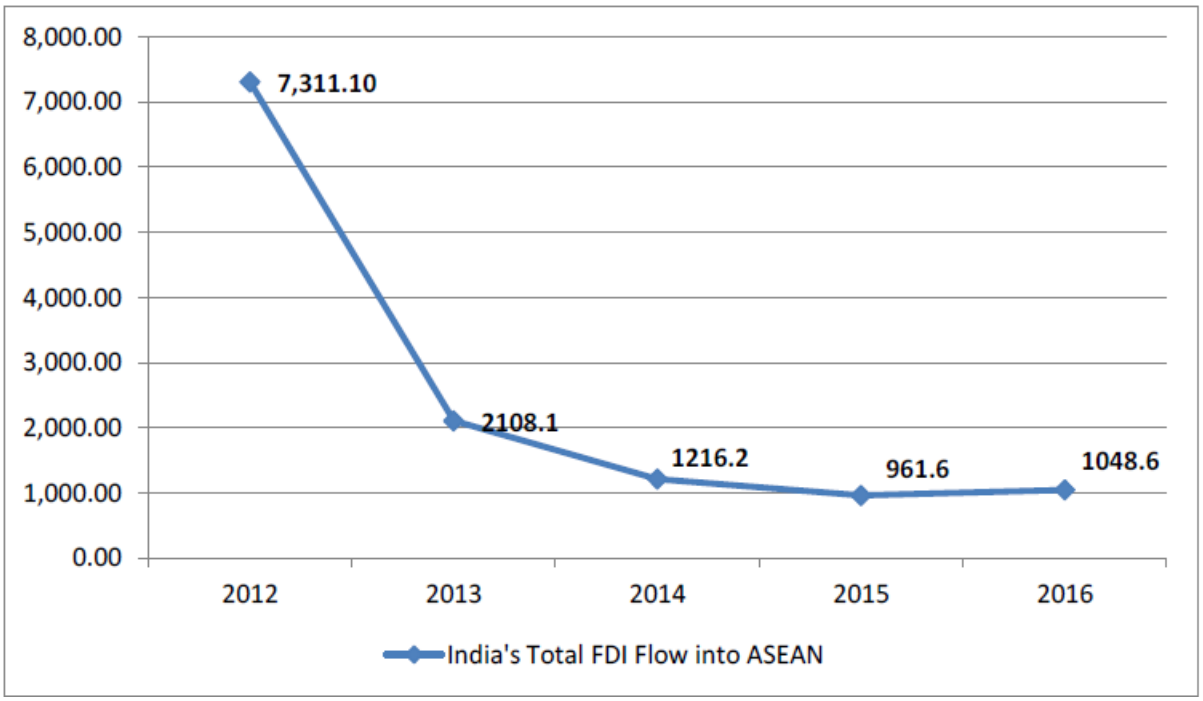

चित्र 2: आसियान में भारतीय एफडीआई प्रवाह, 2012- 2016[iv] **(मिलियन डॉलर)**

उपर्युक्त आंकड़े का ग्राफ 2012-2016 के बीच आसियान में भारत के एफडीआई प्रवाह को इंगित करता है। जैसा कि आंकड़े से देखा जा सकता है, आसियान में भारत के एफडीआई में 7.3 बिलियन डॉलर से अधिक की ऊंचाई आने के बाद 2016 में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिरावट आई है। आसियान निवेश रिपोर्ट 2017 के अनुसार, आसियान में भारतीय एफडीआई में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति ने, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारतीय ओएफडीआई स्टॉक के स्तर को प्रभावित किया है , जो 2010 में 20.8 बिलियन डॉलर से घटकर 2015 में 18.4 बिलियन डॉलर हो गया। नीचे दिया गया पाई चार्ट 2005 से 2015 तक आसियान के विभिन्न उद्योगों में भारत के 53.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के प्रतिशत को दर्शाता है।

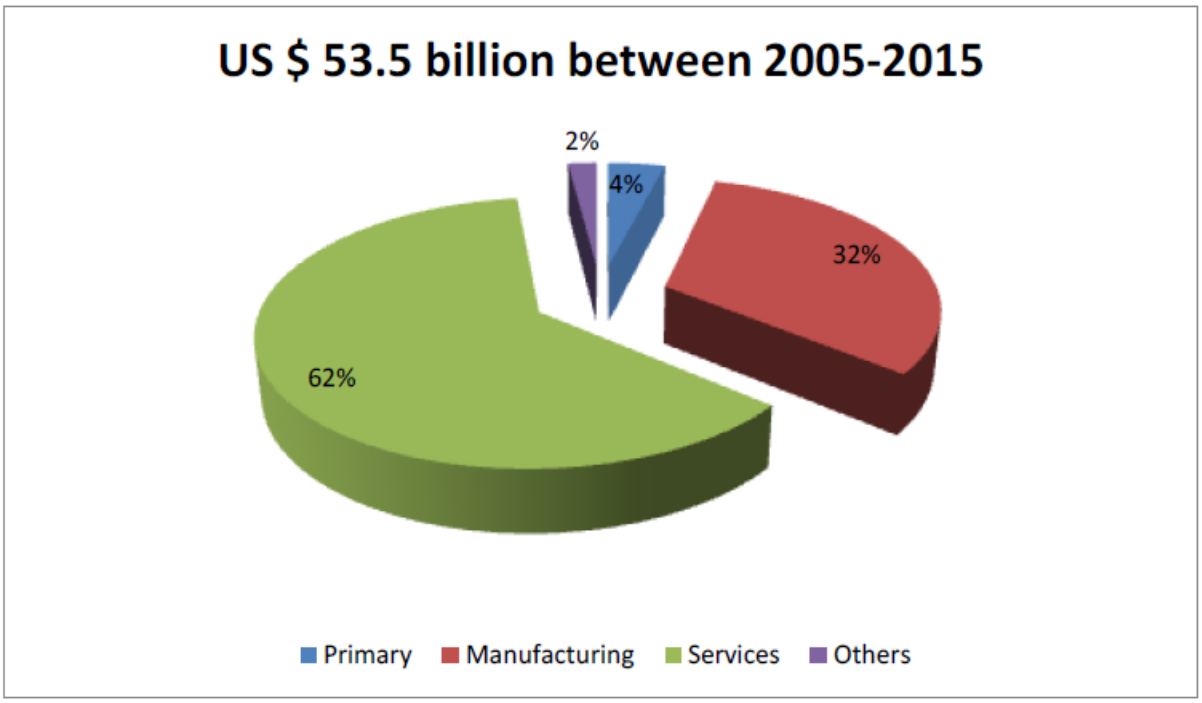

चित्र 3: आसियान में भारतीय प्रवासी निवेश गतिविधियाँ, उद्योगों में, 2005-2015[v] (प्रतिशत में)

यह चित्र दर्शाता है कि आसियान के प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय एफडीआई करीब 4 प्रतिशत था। इसकी निवेश गतिविधियां मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की निकासी में हैं। आसियान में भारतीय विनिर्माण निवेश गतिविधियां प्रौद्योगिकी- गहन उद्योगों में केंद्रित हैं और ओएफडीआई का लगभग 32 प्रतिशत है। 2005 से 2015 के दौरान, मध्यम-प्रौद्योगिकी उद्योग अर्थात् बुनियादी धातु और गढ़े हुए धातु उत्पादों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी थी, इसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जैसे मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरण 34.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ थे। इन दोनों उद्योगों ने क्षेत्र में करीब 72 प्रतिशत ओएफडीआई प्रवाह प्राप्त किया। इसके अलावा, हाल के वर्षों में फार्मास्युटिकल्स में भारतीय निवेश तेजी से बढ़ा है , विशेष रूप से 2015 में। आसियान में सेवाओं में भारतीय निवेश गतिविधियों में 2005 से 2015 के दौरान तेजी से विस्तार हुआ है और यह भारत के कुल ओएफडीआई का 62 प्रतिशत रहा। इन निवेशों का बड़ा हिस्सा संचार सेवाओं में रहा और उसके बाद निर्माण और परिवहन एवं भंडारण में। व्यावसायिक सेवाएँ, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ, और आईटी एवं आईटीई की सेवाएँ भी महत्वपूर्ण हैं और बढ़ रही हैं। आसियान और भारत के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। आसियान 2010-2015 के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी पूंजी में कुल 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत के लिए एफडीआई का प्रमुख स्रोत है , जिसने भारत में 16 प्रतिशत एफडीआई प्रवाह का प्रतिनिधित्व किया। सिंगापुर के पास भारत में एफडीआई की हिस्सेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि आसियान की अधिकांश कंपनियां भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य उद्योगों में सम्मिलित हैं।[vi]

सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ विवियन बालाकृष्णन के अनुसार, आर्थिक संबंधों में वृद्धि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे की आर्थिक क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए किए गए प्रयासों के कारण संभव हुई है। यह संबंध समानता , समावेशिता के साथ- साथ स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि समग्र आर्थिक संबंध उच्च स्तर को प्राप्त कर रहा है , तथापि कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कुल व्यापार के आकार को क्षमता के अनुसार बढाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, निवेश के संदर्भ में, और अच्छा किया जा सकता है। आसियान में 2010-2016 तक भारत का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) योगदान आसियान के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का 1.8% और आसियान के कुल बाहरी व्यापार में 2.6 प्रतिशत रहा है।[vii] इस छोटे प्रतिशत का एक बड़ा कारण यह हो सकता है, जैसा कि विदेशी मंत्री ने उठाया है, कि आसियान में भारत का निवेश भौगोलिक रूप से केंद्रित है, जिसमें अधिकांश गतिविधि कुछ आसियान राज्यों, जैसे कि सिंगापुर में ही केन्द्रित है। भारत के साथ मजबूत हवाई संपर्क , व्यवसाय के पक्ष में माहौल , अधिक स्थिर कराधान प्रणाली, सैन्य और वित्तीय अवसंरचना तथा एक बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय की उपस्थिति जैसे कारक सिंगापुर में भारतीय निवेश के प्रमुख चालक रहे हैं। इसके अलावा, 2005 में भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर हस्ताक्षर ने सिंगापुर और भारत के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को गति प्रदान की है। हालांकि आसियान भारतीय ओएफडीआई के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है। 2010 से 2016 के बीच भारत आसियान में 11वां सबसे बड़ा गैर-आसियान निवेशक था। हालांकि , जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तुलना में आसियान में भारतीय एफडीआई प्रवाह अपेक्षाकृत कम है , कई भारतीय फर्म छोटी ओएफडीआई परियोजनाओं के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं, विशेष रूप से सेवाओं के क्षेत्र में। यह आसियान में भारतीय एफडीआई प्रवाह के अपेक्षाकृत निचले स्तर को भी आंशिक रूप से समझाता है।[Viii]

इसलिए, भौतिक, डिजिटल के साथ-साथ लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो बदले में आसियान राज्यों में से प्रत्येक के साथ आर्थि क संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन से पहले की द्विपक्षीय बैठकों में , भारतीय प्रधानमंत्री और म्यांमार के स्टेट काउंसलर ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के बारे में बात की , जिसमें सिटवे पोर्ट , त्रिपक्षीय राजमार्ग और अन्य सीमापार व्यापार का संचालन शामिल था। वियतनाम के प्रधान मंत्री गुयेन जुआनफुक के साथ बैठक में , दोनों नेताओं ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के परिचालन के बारे में बात की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की पूरी क्षमता के दोहन की आवश्यकता सहित समुद्र किनारे गश्ती जहाजों का निर्माण तथा 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित कर ना शामिल था। फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटर्टे ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग में

रुचि व्यक्त की। दोनों नेताओं ने फिलीपींस में हवाई अड्डे के विकास तथा अन्य अवसंरचनात्मक विकास कार्यों में भारतीय निजी कंपनियों, जैसे कि जीएमआर के महत्व पर चर्चा की।

थाई प्रधानमंत्री चान-ओ-चा के साथ बैठक में, मेकांग-गंगा सहयोग और बिम्सटेक जैसे उप-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, दोनों राष्ट्र पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग के लिए प्रस्ताव भी रख सकेंगे। सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर बल देते हुए दोनों नेताओं ने आईटी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। भारतीय प्रधान मंत्री ने नागरि क उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगापुर की एयरलाइनों को विशेष रूप से गुवाहाटी सहित अन्य भारतीय शहरों में संचालन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। यह पूर्वोत्तर भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। ब्रुनेई के सुल्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक में यह सहमति बनी कि स्वास्थ्य क्षेत्र और आईटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ब्रुनेई ने तेल और गैस क्षेत्र में अधिक से अधिक भारतीय भागीदारी की इच्छा भी व्यक्त की है।[ix]

द्विपक्षीय बैठकें व्यापार, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास की विशाल संभावनाओं पर आसियान तथा भारत की समझ की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा , भारत और आसियान राज्यों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक सहभागिता के इन प्रस्तावों को बिना किसी देरी के साकार करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

सुरक्षा कारक

आसियान भारत के तात्कालिक रणनीतिक क्षेत्र में आता है। अंडमान द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच की भौतिक दूरी केवल 195 किलोमीटर है तथा साथ ही यह म्यांमार और थाईलैंड के साथ बहुत नजदीकी समुद्री सीमाओं को भी साझा करता है। इसके अलावा, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी भौतिक सीमा साझा करता है। ये भौतिक और समुद्री सीमाएं जो भारत को इन तीन राज्यों से जोड़ती हैं , देश को भू-रणनीतिक रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ देती हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति और दक्षिण- पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की ओर भारत के प्रयासों के बाद, सुरक्षा चिंताओं को लेकर भारत की समझ आसियान राज्यों की चिंताओं से मेल खाती है। परिणामस्वरूप 1992 में आसियान के एक क्षेत्रीय भागीदार और 1995 में एक पूर्ण संवाद भागीदार के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय साझेदारी व्यापार , निवेश और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए थी जबकि संवाद साझेदारी ने सहयोग के लिए एक व्यापक एजेंडा प्रदान किया, जिसमें सुरक्षा तथा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग शामिल थे । 1996 में, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) का सदस्य बन गया जिसका उद्देश्य विश्वास बहाली, संघर्ष समाधान और निवारक कूटनीति था। भारत एआरएफ का

सक्रिय सदस्य रहा है और उसने आसियान के साथ खोज और बचाव , समुद्री डकैती और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में काम किया है।[x]

भारत ने अक्टूबर 2003 में आसियान की मित्रता एवं सहयोग की संधि (टीएसी) की, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे ती है। साथ ही यह 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 2010 में स्थापित आसियान रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक प्लस जैसी आसियान सुरक्षा संवाद पहल का हिस्सा भी बन गया है। आसियान की अगुवाई वाले विभिन्न सुरक्षा संवाद पहलों में भारत की पदवृद्धि को भी सुविधाजनक बनाया गया है क्योंकि दोनों ही अहस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों को साझा करते हैं, एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान प्रदर्शित करते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीके से और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विवादों को हल करते हैं।

2012 में भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी की स्थापना ने आसियान के साथ-साथ व्यक्तिगत आसियान राज्यों के साथ सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक मजबूत सहयोग को बल प्रदान किया है। क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने को अपनी प्रतिबद्धता का एहसास करने के लिए कनेक्टिविटी भारत और आसियान के लिए एक आवश्यक तत्व है।

भारत और आसियान राज्य कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भौतिक के साथ- साथ डिजिटल, यानि सख्त के साथ-साथ सरल तरीके से सहयोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, भारत म्यांमार और थाइलैंड के साथ त्रिपक्षीय राजमार्ग का हिस्सा है , जिसे लाओ पीडीआर और वियतनाम तक बढ़ाया जाना है , और जिससे जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी का निर्माण होता है। भारत बंदरगाहों को विकसित करने के काम में भी शामिल है, जिनका इन राष्ट्रों के रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही यह वियतनाम में अपतटीय तेल ड्रिलिंग में भी शामिल है।

दशकों से भारत और व्यक्तिगत आसियान राज्य कई क्षेत्रीय और उप- क्षेत्रीय प्लेटफार्मों में साथ रहे हैं, जिन्होंने एक तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में उनके सहयोग को मजबूत करने में मदद की है। संबंधों के 50 साल को चिह्नित करने के लिए , द्विपक्षीय रूप से भारत 24 नवंबर 2015 को स्थापित भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी जैसे आसियान राज्यों के साथ अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। इसके अलावा , सितंबर 2016 में जब भारतीय प्रधान मंत्री ने वियतनाम का दौरा किया , तो हनोई के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गयी जिसके तहत भारत-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष रक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा की गई। जनवरी 2018 में, भारत और इंडोनेशिया के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए नियमित तंत्र को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई। 25 जनवरी, 2018 को राष्ट्रपति डुटर्टे के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में आतंकवाद विरोध पर

महत्वपूर्ण चर्चा हुई जिसमें विशेष रूप से शहरी आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर बात की गयी। दोनों नेताओं ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और इस तरह की प्रसार गतिविधियों में शामिल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और गठजोड़ को लेकर साझा तौर पर चिंता जाहिर की। इसके अलावा , थाईलैंड के प्रधान मंत्री के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा में अधिक सहयोग, नियमित जहाज यात्राओं और अभ्यासों को बढ़ाने तथा रडार प्रणाली एवं अपतटीय जहाजों के माध्यम से तटीय निगरानी में सहयोग के संदर्भ में भी चर्चा की गई। xi

इस यादगार शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खतरे , समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर स्वत: ही विवेचना की गयी , जिसपर भाग लेने वाले सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के साथ-साथ कट्टरपंथीकरण का मुकाबला करने के लिए सामूहिक रू प से काम करने पर सहमति व्यक्त की। आसियान राज्यों मलेशिया और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के नरम और कठिन पहलुओं से निपटने के अपने अनुभवों और अपने देशों में शुरू किए गए कानूनों के बारे में चर्चा की। अपने सफल कार्यक्रमों और विधानों के माध्यम से दोनों राष्ट्र अपने युवाओं में कट्टरपंथीकरण को कम करने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा , समुद्री सहयोग को बढ़ा ने से मानवीय आपदा राहत, सुरक्षा सहयोग और नौ परिचालन की स्वतंत्रता सहित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने की अधिक संभावना बनेगी। xii भारत आसियान की केंद्रीयता का प्रबल समर्थक रहा है , और क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे में आसियान की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करता है। भविष्य में, भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए , भारत और आसियान के बीच बढ़ता रणनीतिक तालमेल क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से अभिन्न अंग साबित होगा।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में विदेश मंत्रालय ने दो झांकियां प्रस्तुत कीं जो इस बात का प्रमाण है कि भारत और आसियान अपने सभ्यतागत संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत और निरंतर सांस्कृतिक संबंधों ने सहयोग के वर्तमान और नए उभरते क्षेत्रों में मंच के निर्माण के लिए आधार प्रदान किया है। आज, भारत और आ सियान के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग में मानव संसाधन विकास , विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी), लोगों से लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, परिवहन और बुनियादी ढांचा, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), पर्यटन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), कृषि, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और आसियान एकीकरण के लिए (IAI) शामिल हैं।xiii

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण एवं बौद्ध तथा इस्लाम द्वारा स्थापित विशिष्ट जुड़ाव कई शताब्दियों से भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के

बीच एक साझा विरासत बने हुए हैं ।[xiv] आसियान और भारत क्षमता निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं , और इस क्षेत्र में बसे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं , साथ ही आसियान राष्ट्र भारतीयों के लिए एक आम पर्यटन स्थल रहे हैं। भारत कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर और वियतनाम में ऐतिहासिक स्मारकों के पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। 20 जनवरी, 2017 को जकार्ता में आसियान-भारत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी जुड़ाव पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, आसियान और भारत के बीच मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया , तथा लोगों से लोगों के जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की चुनौतियों को दूर करने के लिए व्यवहा र्य नीति विकल्पों की पहचान करने पर बल प्रदान किया गया।[xv] अंतर-सांस्कृतिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भिन्नताओं को पाटने और आपसी जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण हैं , तथा आसियान और भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय के उप महासचिव वोंगटेपअर्थाकाईवलवेटे, ने भी अंतर संस्कृति संवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र को बाँध कर रखने वाले सांस्कृतिक ताने-बाने पर जोर दिया।[xvi]

भारत और आसियान दोनों देशों के नेतृत्व ने समान रूप से एक-दूसरे के करीब आने की जरूरत महसूस की है। भारत-आसियान संबंधों में सामाजिक- सांस्कृतिक जुड़ाव का महत्व इस तथ्य को देखते हुए बहुत स्पष्ट है कि आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा है । इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सर्किट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। प्रस्तावित बौद्ध पर्यटन सर्किट महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह क्षेत्र में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा। नींव के रूप में , सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के साथ, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है , आसियान राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध स्थायी प्रगति और समृद्धि के माध्यम से आज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये तीन तत्व व्यापक भारत-आसियान संबंधों का हिस्सा हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं; और नित नए क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक बना रहे हैं। आसियान-भारत संवाद साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर 25 जनवरी, 2018 को आसियान-भारत स्मारक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आसियान के सभी दस प्रमुखों को नई दिल्ली आमंत्रित किया गया, जबकि वे सभी 26 जनवरी, 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

द रिट्रीट: भारत-आसियान समुद्री सहयोग और सुरक्षा

औपचारिक शिखर सम्मेलन से पूर्व, पहली बार भारत और दस आसियान प्रमुखों एवं सरकारों के बीच एक बैठक आयोजित की गई , जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना था। यह शिखर सम्मेलन के एक प्रमुख परिणाम के रूप में उभरा है और

संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि इसमें भारत और आसियान के बाकी राज्यों के जलीय क्षेत्रों के बीच साझा किए गए हितों और चिंताओं का समन्वय है।

बदलती रणनीति के कारण सुरक्षा की अवधारणा में बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्यों के बीच संबंधों को परिवर्तित कर दिया है। इस अवधारणा में अपनाई जा रही रणनीति भी शामिल है, जहां विरोधी अब राज्यों में प्रतिबंधित नहीं हैं। इससे समुद्री सुरक्षा की समग्र समझ में भी बदलाव आया है, क्योंकि यह विशाल और निर्जन पानी का प्रतिनिधित्व करता है जो क्षेत्रीय और साथ ही वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी समुद्री संचार पर अधिक से अधिक निर्भर हो गई है, और जैसे-जैसे भूमि आधारित संसाधन कम होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पूरा ध्यान अपतटीय हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ गहरे समुद्र के संसाधनों की संभावनाओं पर केन्द्रित हो गया है। व्यक्तिगत राज्यों के विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता ने देश के क्षेत्रीय जल और ईईजेड के संरक्षण पर जोर दिया है। नई तकनीकों के विकास तथा समुद्री संसाधनों एवं थलीय जीवन शैली के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता ने समुद्री सुरक्षा के दायरे को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत आम तौर पर मानव जाति की चिंता शामिल है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अवैध और अत्यधिक मत्स्यपालन, पर्यावरण सुरक्षा, समुद्री संसाधनों और पारिस्थितिकी का संरक्षण।[xvii]

भारत 7500 किमी से अधिक की तटीय रेखा के साथ हिंद महासागर के केंद्र में स्थित एक समुद्री राष्ट्र है और 200 समुद्री मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की घोषणा के बाद, इसके ऊपर दो मिलियन वर्गकिलोमीटर से अधिक के अपने पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित रखने का दायित्व है। इस प्रकार, भारत को अपने आर्थिक और रणनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। भारत ने मजबूत समुद्री हित विकसित किया है और यह नौ परिचालन की स्वतंत्रता की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए समुद्र के खुले और नि:शुल्क उपयोग के विकास की वकालत कर रहा है, जो पूरे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।[xviii]

9/11 के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया में आतंकवादी हमले की बढ़ती घटनाओं ने इस क्षेत्र में कट्टरपंथी चरमपंथ के खतरों को उजागर कर दिया है। इसके अलावा, मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले, जब आतंकवादियों ने समुद्र से हमला किया था, के भारत के अपने अनुभव ने, छिद्रपूर्ण समुद्री सीमा के खतरों का संकेत दे दिया था। इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, अंडमान सागर, मलक्का जलडमरूमध्य और इंडोनेशिया के आसपास के समुद्री क्षेत्र में नार्को-आतंकवाद, समुद्री डकैती और अवैध शिकार से संबंधित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इन समस्याओं में कम तीव्रता का सशस्त्र संघर्ष, संचार के समुद्री गलियारों की सुरक्षा को खतरा तथा समुद्री संसाधनों के सामूहिक और उत्तरदायी शोषण शामिल हैं।[xix]

भारत के समुद्री जगत को सुरक्षित बनाने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए , शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान नेताओं के लिए आयोजित रिट्रीट में समुद्री सुरक्षा और सहयोग के विषय पर चर्चा की गई। रिट्रीट में, पीएम और आसियान नेताओं ने समुद्री सहयोग के लिए एक तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की , जो पारंपरिक और गैर- पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रकार, दोनों पक्षों ने आतंकवाद- रोधी, ड्रग्स, समुद्री डकैती, और समुद्री सुरक्षा के लिए अन्य चुनौतियों के मौजूदा क्षेत्रों में संलग्न रहने के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विस्तार की आवश्यकता को साझा किया। भारत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए समुद्री संपर्क में तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। प्रस्तावित भारत- आसियान समुद्री परिवहन समझौता आसियान राज्यों के साथ अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भारत के लिए एक ऐसा ही तंत्र है। प्रस्तावित समझौते के शीघ्र निष्पादन से समुद्री परिवहन में अवरोध उत्पन्न करने वाली बाधाओं को समाप्त करने में मदद मिलेगी तथा एक क्षेत्रीय परिवहन ढांचे की स्थापना हो सकेगी जिसका उद्देश्य भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे की समुद्री परिवहन सुविधा को बढ़ाना होगा।[xx]

गैर-राज्य संस्थाओं से बढ़ते खतरे ने भारत और आसियान को अपने समुद्री स्थान में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक और साझा मंच प्रदान किया है। भारत-आसियान सहयोग के इस स्वरूप को न केवल खतरों का मुकाबला करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत होगी जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक- दूसरे की संबंधित क्षमताओं को मजबूत करने में मदद भी करेगी।[xxi]

आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के परिणाम: दिल्ली घोषणापत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान राज्यों के 10 प्रमुखों ने आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के अंत में दिल्ली घोषणापत्र को जारी किया, जो *"साझा मूल्य, साझा नियति"* विषय पर आधारित था।

- आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बढ़ते हुए भारत और आसियान ने कार्य योजना (2016-20) के पूर्ण और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सदस्यों ने 'आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता और पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के तेजी से निष्पादन की मांग की। हालांकि, वे प्रक्रिया को बाधित करने वाली अड़चनों को दूर करने का मार्ग नहीं ढूंढ पाए।[xxii] दोनों पक्ष व्यापार, पर्यटन और निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए विमानन और समुद्री परिवहन को मजबूत करने पर सहमत हुए। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाना जारी रखते हुए, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए , उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

और बाहरी अंतरिक्ष एवं इसके अनुसंधान तथा विकास के शांतिपूर्ण अन्वेषण पर जोर दिया।[xxiii] उन्होंने विकास के अंतर को कम करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने और आसियान सामुदायिक विजन 2025 को लागू करने में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।[xxiv]

- रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में , भारत और आसियान दोनों ने आम क्षेत्रीय और सुरक्षा मुद्दों के साथ- साथ समुद्री संसाधनों , समुद्री व्यापार मार्गों और परिवहन के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आतंकवादी समूहों और संगठनों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्लेटफार्मों को मजबूत करने , इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुकाबला करने, आतंकवाद के वित्तपोषण, आतंकवादी भर्ती, और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त रूप से समुद्री चुनौतियों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

- सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में दोनों पक्षों के नेताओं ने अपने सामान्य ऐतिहासिक और सभ्यतागत जुड़ावों की समझ को और मजबूत करने के लिए मंच के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। पारस्परिक हितों वाले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों और संरचनाओं को पुन: बहाल करने की दिशा में सहयोग पर बल दिया गया है, जबकि सांस्कृतिक पर्य टन को बढ़ावा दे ने पर भी जोर दिया जा रहा है । उन्होंने युवाओं और किसानों सहित समाज के सभी क्षेत्रों से विनिमय कार्यक्रमों का भी आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा केंद्रों और तकनीकी एवं आर्थिक सहकारी संस्थानों की स्थापना तथा विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति की उपलब्धता, शोध एवं व्यावसायिक शिक्षा को लेकर दृढ़ता से अपनी बात रखी ।[xxv] इसके अलावा, भारत और आसियान ने आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में सहयोग को मजबूत करने के लिए स्थापित तंत्र के भीतर बेहतर समन्वय की बात की।[xxvi]

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि शिखर सम्मेलन के दिल्ली घोषणापत्र ने दोनों पक्षों के बीच अधिक से अधिक राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। नई दिल्ली में दस आसियान नेताओं की मौजूदगी को केवल भारत-आसियान संबंधों के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने की कवायद के रूप में नहीं देखा जा सकता है , बल्कि यह आपसी सहयोग के क्षेत्रों को मजबूत करते हुए तथा मौजूदा संबंधों में और अधिक गतिशीलता लाने के लिए चुनौतियों और अड़चनों की पहचान करने के लिए भारत और आसियान दोनों का एक संयुक्त प्रयास है। भारत-आसियान समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने पर जोर

देना भविष्य के सहयोग और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के नवीनीकरण के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करता है। भारत और उसके विस्तारित पड़ोस की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। 'एसएजीएआर' 'सागर' की अवधारणा को, जिसका अर्थ 'क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास ' है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2016 में जारी किया था, और यह आसियान को प्रवेश द्वार मानते हुए पूरे भारत-प्रशांत क्षेत्र पर लागू होता है। भारत और आसियान के बीच आपसी विश्वास के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में रुचि की साझा समानता को देखते हुए, यह पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग का मार्ग प्रदान करता है। इस प्रकार , भारत-आसियान अपने समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए नए उत्प्रेरक बन सकते हैं जो आने वाले वर्षों में भारत-आसियान संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं; इस प्रकार क्षेत्र के भीतर और बाहर सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावना को बल प्रदान करते हुए संबंधों को दृढ बनाया जा सकता है।

****

**डॉ तेम्जेनमेरेनएओ तथा डॉ ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, रिसर्च फेलो, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली।*
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद के नहीं।

अंत टिप्पण

iGanganath Jha, India and Southeast Asia: Introspection for Future Partnership, (Anamika Publishers & Distributors Ltd: Delhi, 2010), p.47-48.

ii"ASEAN Trade in Goods (in US $)", ASEAN stats, https://data.aseanstats.org/trade.php, accessed on February 19, 2018.

iii"India ASEAN Trade and Investment Relations: Opportunities and Challenges", The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, July 2016, http://www.assocham.org/upload/docs/ASEAN-STUDY.pdf, accessed on February 19, 2018.

iv "ASEAN Investment Report 2017: Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN", The ASEAN Secretariat, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2017d1.pdf, accessed on March 21, 2018.

v Reserve Bank of India, See: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2017d1.pdf, accessed on March 21, 2018.

vi Ibid.

vii Ministry of Foreign Affairs, Singapore, 'Transcript of Keynote Address By Minister for Foreign Affairs Dr Vivian Balakrishnan at the ASEAN-India Pravasi Bharatiya Divas Opening Plenary, Sunday, January 7, 2018, Marina Bay Sand', at https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201712/Press_20180107.html accessed on February 13, 2018

viii"ASEAN Investment Report 2017: Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN", The ASEAN Secretariat,

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2017d1.pdf, accessed on March 21, 2018.

ix"Transcript of Media Briefing by Secretary (East) on ASEAN-India Commemorative Summit (January 25, 2018)", Ministry of External Affairs, January 26, 2018, http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/29392/Transcript+of+Media+Briefing+by+Secretary+East+on+ASEANIndia+Commemorative+Summit+January+25+2018, accessed on March 21, 2018.

xGanganath Jha, India and Southeast Asia: Introspection for Future Partnership, (Anamika Publishers & Distributors Ltd: Delhi, 2010), p.46-47.

xi "Transcript of Media Briefing by Secretary (East) on ASEAN-India Commemorative Summit (January 25, 2018)", Ministry of External Affairs, January 26, 2018, http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/29392/Transcript+of+Media+Briefing+by+Secretary+East+on+ASEANIndia+Commemorative+Summit+January+25+2018, accessed on March 21, 2018.

xii "Transcript of Media Briefing on ASEAN-India Commemorative Summit (January 26, 2018)", Ministry of External Affairs, http://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl%2F29399%2FTranscript_of_Media_Briefing_on_ASEANIndia_Commemorative_Summit_January_26_2018=, accessed on march 21, 2018.

xiii "Overview – ASEAN India Dialogue", Ministry of External Affairs, Government of India, February 2017, http://asean.org/storage/2012/05/Overview-ASEAN-India-as-of-February-2017r4CL.pdf accessed on February 15, 2018

xiv Opening remarks by the PM at the Plenary Session of the INDIA- ASEAN Commemorative Summit (January 25, 2018), Ministry of External Affairs, Government of India, http://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29390/Opening_remarks_by_the_PM_at_the_Plenary_Session_of_the_INDIA_ASEAN_Commemorative_Summit_January_25_2018 accessed on February 20, 2018

xv "ASEAN, India to boost cultural cooperation and linkages", Official ASEAN Website, January 20, 2017, http://asean.org/asean-india-to-boost-cultural-cooperation-and-linkages/ accessed on February 15, 2018

xvi "ASEAN, India to boost cultural cooperation and linkages", Official ASEAN Website, January 20, 2017, http://asean.org/asean-india-to-boost-cultural-cooperation-and-linkages/ accessed on February 15, 2018

xviiVibhanshu Shekhar, "India's Maritime Security and ASEAN: Issues of Narcoterrorism , Piracy and Poaching", in P V Rao (edi), India and ASEAN: Partners at Summit, (Knowledge World: New Delhi, 2008), p. 195-196.

xviiibid, p. 197.

xixibid.

xxDipanjan Roy Chaudhury, "India, ASEAN leaders agree to boost maritime cooperation", The Economic Times, January 28, 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-asean-leaders-agree-to-boost-maritime-cooperation/articleshow/62654982.cms, accessed on February 12, 2018.

xxi Lt Gen Y M Bammi (Retd), India and South East Asia: The Security Cooperation, (Gyan Publishing House: New Delhi, 2006), p. 211-216.

xxii Delhi Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to mark the 25th Anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations, Press Information Bureau, Government of India, Prime Minister's Office, January 25, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175908 accessed on January 26, 2018

xxiii Ibid

xxiv Ibid

xxv Ibid

xxvi Ibid